बजट अनालीसिस एण्ड रिसर्च सेंटर ट्रस्ट, जयपुर

राजस्थान बजट 2026-27 के लिए कुछ सुझाव

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

विकसित राजस्थान 2047 में सरकार द्वारा सरकार ने राजस्थान में सभी नागरिकों के लिए साफ हवा, बढ़े हरित क्षेत्र एवं टिकाऊ एवं स्वस्थ्य पर्यावरण का सराहनीय लक्ष्य बनाया है । इस दिशा में निम्न निवेदन है कि

1. राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष से ग्रीन बजट जारी करना प्रारंभ किया किया गया है जो अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम है । ग्रीन बजट की प्रक्रिया को और मजबूत बनाते हुए आने वाले वर्षों में आवंटित बजट के उपयोग को भी ग्रीन बजट में शामिल किया जाएगा ।
2. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम राजस्थान के 5 शहरों में लागू है । लेकिन राज्य के अन्य शहर और ग्रामीण क्षेत्र भी वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं। अतः राज्य सरकार पूरे प्रदेश में स्वच्छ वायु के लिए योजना बना कर एक समुचित कार्यक्रम को लागू करे।
3. इस संबंध में राज्य में पहले से भी बने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना, 2022; राज्य जलवायु परिवर्तन नीति, 2023; राज्य पर्यावरण योजना 2022 और सभी जिलों के जिला पर्यावरण योजना बने हुए हैं । लेकिन राज्य पर्यावरण योजना को छोड़ कर अन्य योजनाओं और कार्यनीति के लागू होने के संबंध में विशेष जानकारी आम तौर पर उपलब्ध नहीं है। कृपया इन नीतियों और कार्य योजना के क्रियान्वयन की जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कारवाई जाए ।

केयर (देख भाल) ईकोनॉमी नीति की घोषणा

समाज में बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों आदि के देखभाल का कार्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है और विशेषकर बिना किसी भुगतान के होने वाला देखभाल (unpaid care) अधिकतर महिलायें ही करती हैं । भारत सरकार द्वारा जारी किए गए समय उपयोग स[/र्वेक्षण (Time Use Survey) ने भी इसे स्पष्ट रूप से दिखाया है । महिलाओं के श्रम बल भागीदारी कम होने यह का एक मुख्य

कारण है । राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान के तहत महिलाओं के श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है जो अत्यंत महत्त्वपूर्ण है ।

इस दिशा में हमारा सुझाव है की राज्य सरकार विस्तृत विचार विमर्श कर राज्य के लिए एक केयर ईकोनॉमी नीति बनाए जिसमें केयर कार्य और केयर कर्मियों से संबंधित स्पष्ट प्रावधान हों । इस नीति में अनपेड केयर कार्यों में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के उपाय; आंगनवाड़ी, पालना जैसी योजनाओं की मज़बूती; और ज़रूरतमंद बुजुर्गों और भिन्न क्षमता वाले ज़रूरतमंद व्यक्तियों की देखभाल के लिए केयर क्लस्टर भी हो सकते हैं । इसके लिए विभिन्न संबंधित योजनाओं के कॉनवर्जन के उपाय भी किए जा सकते हैं ।

राजस्थान रोज़गार नीति

पिछले बजट में की गई घोषणा के अनुसार राज्य सरकार एक राजय रोज़गार नीति भी लाने वाली है। आशा है इस नीति की घोषणा जल्द की जाएगी और विवेकानंद रोज़गार कोश भी कार्यशील किया जाएगा।

ग्रामीण रोज़गार गारंटी

विबी जी राम जी अधिनियम को लागू करने हेतु इसके बजट में राज्य सरकार का हिस्सा बढ़ाने की ज़रूरत होगी। ऐसे में राज्य सरकार इस कानून को लागू करने हेतु राज्य का हिस्सा पिछले वर्ष के की अपेक्षा कम से कम दुगुना या उससे अधिक रखे।

पंचायतों का डिजिटल प्रशिक्षण

राज्य में शासन के काम काज अधिक से अधिक डिजिटल हो रहा है । हाल ही में पारित विबी जी राम जी अधिनियम में भी ग्रामीण रोज़गार गारंटी को लागू करने में डिजिटल प्रणाली पर अत्यधिक जोर है । ऐसे में पंचायत कर्मियों के डिजिटल प्रशिक्षण के लिए एक सघन अभियान चलाया जाना चाहिए ।

शहरी निकायों में आयोजना एवं जेंडर बजट

संविधान में ग्राम पंचायतों की तरह शहरी निकायों द्वारा भी प्रति वर्ष "आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय" के लिए आयोजना बनाने का प्रावधान है । एक तरफ जहां पंचायतों को योजना बनाने हेतु प्रशिक्षण एवं दिशानिर्देश एवं निर्देशिका उपलब्ध रहते हैं वहीं दूसरी तरफ शहरी निकायों को आयोजनाकरने हेतु प्रशिक्षण एवं इसके लिए सरकार द्वारा एक समुचित एवं व्यवस्थित निर्देशिका का अभाव दिखता है । ऐसे में हमारा सुझाव है कि शहरी निकायों के लिए आयोजना बनाने के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाए और एक समुचित निर्देशिका भी जारी की जाए ।

साथ ही राज्य सरकार से आग्रह है की राज्य के शहरी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को मज़बूती देने के लिए राज्य के शहरी निकायों में भी जेन्डर बजट की प्रक्रिया को लागू करे ।

राज्य सरकार द्वारा एक गुड गवर्नन्स बिल

राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान का रोडमैप तैयार किया है। विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने हेतु राज्य में कुशल शासन प्रणाली को बढ़ावा देने एके लिए राज्य सरकार एक एक गुड गवर्नन्स बिल लाए, जिसकी पहले भी चर्चा होती रही है । राजस्थान सरकार यह विधेयक लाती है तो राजस्थान लाने वाली संभवतः देश का पहला राज्य होगा जहां ऐसा विधेयक पारित होगा । इससे राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में अत्यधिक सहायता होगी ।